

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए



19th October 2022



FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

 Guru Deekshaa Hindi



INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

19th October 2022

1. - एफएटीएफ के बारे में:	3
(i) एफएटीएफ:	3
(ii) FATF के दायित्वों में शामिल हैं:	3
(iii) FATF के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:	3
2. - एके 203 असॉल्ट राइफल्स का विवरण:	4
(i) के बारे में:	4
(ii) AK-203 के फायदे और ताकत:	4
3. - समान नागरिक संहिता के बारे में:	5
(i) के बारे में:	5
(ii) संवैधानिक प्रावधान जो यूसीसी को संदर्भित करते हैं:	5
(iii) समान नागरिक संहिता का इतिहास:	6
(iv) यूसीसी औचित्य:	6
(v) यूसीसी आलोचनाओं में शामिल हैं:	6
(vi) अगले कदम:	6
4. - जीआई टैग का विवरण:	7
(i) के बारे में:	7
(ii) जीआई टैग के लाभ:	7



संपादकीय विश्लेषण 8

1. पुलिस सुधार: 8

(i) पुलिस सुधारों का महत्व और आवश्यकता: 8

(ii) आगे बढ़ना: 8

2. विदेशी मुद्रा भंडार: 10

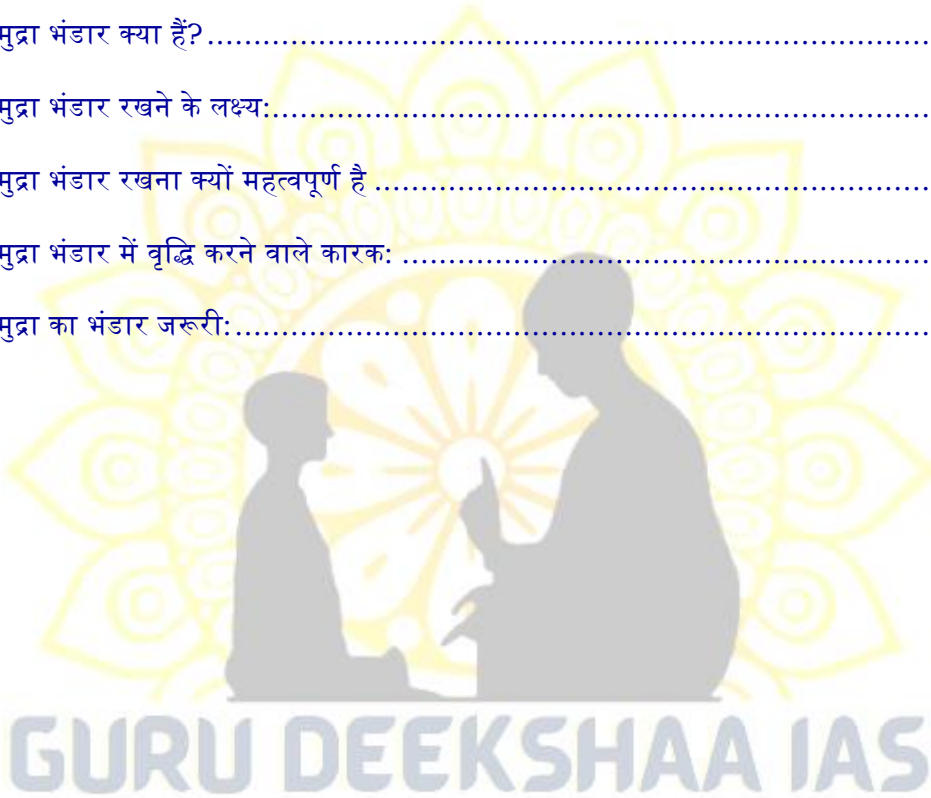
(i) विदेशी मुद्रा भंडार क्या हैं? 10

(ii) विदेशी मुद्रा भंडार रखने के लक्ष्य: 10

(iii) विदेशी मुद्रा भंडार रखना क्यों महत्वपूर्ण है 10

(iv) विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने वाले कारक: 11

(v) विदेशी मुद्रा का भंडार जरूरी: 11





1. - एफएटीएफ के बारे में:

GS II

विषय→अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध:

➤ संदर्भ:

- इस सप्ताह पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पूर्ण सम्मेलन में, पाकिस्तान को समूह की "ग्रे सूची" से हटा दिए जाने का अनुमान है, हालांकि आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के अपने प्रयासों पर सदस्यों को अभी भी अपडेट करने की आवश्यकता होगी। भारत इस पसंद पर कड़ी नजर रखेगा।

एफएटीएफ:

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (FATF) की पुलिसिंग के प्रभारी अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम है।
- वैश्विक नियम स्थापित करके, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य इन अवैध व्यवहारों और समाज को होने वाले नुकसान को मिटाना है।
- नीति-निर्माण निकाय के रूप में अपने कार्य के एक भाग के रूप में, FATF इस प्रकार के राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधारों को पूरा करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति विकसित करना चाहता है।
- आतंकवाद, संगठित अपराध और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को सक्षम करने के लिए, FATF ने FATF अनुशंसाएँ बनाई, जिन्हें अक्सर FATF मानकों के रूप में जाना जाता है।
- वे अवैध ड्रग्स की बिक्री और मानव तस्करी सहित अपराधों को अंजाम देने के लिए अपराधियों द्वारा

उपयोग किए जाने वाले धन को ट्रैक करने में कानून प्रवर्तन की सहायता करते हैं।

- FATF WMDs, विशेष रूप से परमाणु हथियारों के लिए वित्तीय सहायता को रोकना चाहता है।

FATF के दायित्वों में शामिल हैं:

- FATF उभरते खतरों से निपटने के लिए नियमित रूप से अपने मानकों में बदलाव करता है। ऐसा ही एक क्षेत्र, जो तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि क्रिप्टोकॉरेंसी लोकप्रियता हासिल कर रही है, वह है आभासी संपत्ति का विनियमन। FATF आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के वित्तपोषण के लिए तकनीकों की भी जांच करता है।
- एफएटीएफ मानकों के पूर्ण और कुशल कार्यान्वयन की देखरेख करके, एफएटीएफ गैर-अनुपालन वाले देशों को जवाबदेह ठहराता है।

FATF के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के प्रायोजन और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य खतरों को रोकने के लिए, न्यायिक, प्रशासनिक और परिचालन प्रक्रियाओं के उचित उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- स्रोत→ हिन्दू



2. - एके 203 असॉल्ट राइफल्स का विवरण:

AK-203 के फायदे और ताकत:

GS III

विषय→आंतरिक सुरक्षा:

➤ संदर्भ:

- एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी का दावा है कि 2022 के अंत तक, उत्तर प्रदेश के कोरवा में भारत-रूस संयुक्त उद्यम एके-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू कर देगा।

के बारे में:

- AK-203 असॉल्ट राइफल को AK-47 का सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से परिष्कृत पुनरावृत्ति माना जाता है।
- यह एक AK-100 राइफल है जिसमें 7.6239mm राउंड (एक जो AK-74M सिस्टम, कई कार्ट्रिज और लंबाई में प्रदान करता है) के साथ है।
- इस संस्करण को भारतीय लघु शस्त्र प्रणाली (INSAS) 5.5645 मिमी असॉल्ट राइफल को बदलने की योजना है, जिसका उपयोग वर्तमान में सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ-साथ अन्य सुरक्षा बलों द्वारा किया जाता है।
- इंसास हथियार के उच्च ऊंचाई वाले उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है। इन राइफलों में जाम, तेल रिसाव और अन्य मुद्दों का भी खतरा होता है।

- अपनी लोकप्रियता और उपयोगकर्ता-मित्रता के कारण, इन तोपों ने अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों में परीक्षणों का सामना किया है।
- यह विशेष मॉडल 30-दौर की पत्रिका के साथ एक बेहतर AK-47 है।
- क्योंकि वे एके लाइन के उत्पाद हैं, इंसास तोपों के विपरीत, ये राइफलें कभी जाम नहीं करतीं।
- ये बंदूकें, जो कलाशिकोव राइफल्स के संशोधन हैं, रेत, गंदगी, पानी और खराब मौसम के माध्यम से आग लगा सकती हैं।
- ये हथियार उच्च स्तर के अनुकूलन, अनुकूलन और बहुमुखी प्रतिभा भी प्रदान करते हैं।
- AK-203 राइफल्स का अधिक शक्तिशाली 7.62 मिमी नाटो मानक गोला बारूद।
- स्वचालित और अर्ध-स्वचालित सेटिंग्स में, राइफल प्रति मिनट 600 राउंड या प्रति सेकंड 10 गोलियां दाग सकती है।

• स्रोत→ हिन्दू



3. - समान नागरिक संहिता के बारे में:

GS II

विषय→सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप:

➤ संदर्भ:

- अन्य धर्मों और संप्रदायों के लोग जो अलग-अलग संपत्ति और विवाह नियमों का पालन करते हैं, वे "राष्ट्र की एकता का अपमान" हैं। समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद 44, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रशासन के तर्क के अनुसार, धर्म को सामाजिक संबंधों और कानून से अलग करता है।

के बारे में:

- समान नागरिक संहिता यह सुनिश्चित करती है कि सभी राष्ट्रीय लोग एक ही व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित हों। यह कोड, जो भारत में मौजूद मौजूदा धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करेगा, एक एकल, सार्वभौमिक मानक स्थापित करेगा जो सभी के लिए लागू किया जाएगा, भले ही वे पूजा करना चुनते हों। "यूसीसी" संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता के लिए है। इसका सीधा सा मतलब है कि, किसी भी विशिष्ट धर्म के अपवाद के साथ, पूरे देश में जीवन के हर पहलू को एक ही कानून नियंत्रित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44, भाग 4 में "समान नागरिक संहिता" का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है।

- एक समान नागरिक संहिता को अपनाने से देश के विविध लोगों को समायोजित करने की क्षमता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता प्रभावित होती है।

संवैधानिक प्रावधान जो यूसीसी को संदर्भित करते हैं:

अनुच्छेद 44:

- एक यूसीसी मौजूद होना चाहिए क्योंकि संविधान की आवश्यकता है "राज्य को भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक सुसंगत नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।"
- इसे प्रकृति में सलाहकार के रूप में माना जाता है क्योंकि यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर अध्याय के अंदर निहित है।

अनुच्छेद 37:

- का मानना है कि हालांकि भारतीय संविधान में एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध होने के बावजूद, एक एकल नागरिक संहिता न तो संविधान द्वारा दी गई गारंटी है और न ही मौलिक अधिकार है।
- UCC प्राप्त करने के लिए मुकदमेबाजी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद जज अभी भी अपनी राय रखते हैं।



समान नागरिक संहिता का इतिहास:

- औपनिवेशिक भारत के बाद से, एक सार्वभौमिक नागरिक संहिता बनाने की धारणा गहन चर्चा का विषय रही है। इस अवधारणा को पहली बार 1835 में ब्रिटिश सरकार द्वारा विदेशों में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने और न्याय प्रशासन को बढ़ाने की योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तावित किया गया था। देश को आजादी मिलने से पहले (औपनिवेशिक युग के दौरान) आपराधिक कानूनों को विकसित और समान रूप से लागू किया गया था। भले ही कई कस्बों में कानून समान थे, लेकिन हर एक की जांच की जा रही थी।

यूसीसी औचित्य:

- यदि राष्ट्रीय संहिता के परिणामस्वरूप हर कोई समान नागरिक मानकों को बनाए रख सके तो संघर्ष कम हो जाएगा।
- यदि और जब आस-पड़ोस के सभी लोग समान मानकों के अनुसार शुरू करते हैं, तो संभावना है कि शांति में सुधार होगा और इतने दंगे नहीं होंगे।
- महिला अधिकार और धर्मनिरपेक्षता: यूसीसी देश की धर्मनिरपेक्ष नींव के पक्ष में लिंग और धर्म के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करने की कोशिश करेगी।
- महिलाओं के सम्मान के जीवन के अधिकारों की रक्षा करने और उनके शरीर और उनके जीवन दोनों पर नियंत्रण रखने के लिए, यूसीसी इसलिए सभी समुदायों को एक साथ ला सकता है।
- कई हानिकारक, अनुचित, और अन्यायपूर्ण समारोह और प्रथाएं जो वर्तमान में विविध संस्कृतियों में प्रचलित हैं, एक तार्किक, समान और सामान्य व्यक्तिगत कानून को अपनाने के साथ समाप्त की जा सकती हैं।

- उदाहरण के लिए, ऐसे कानून जो हाथ से मैला ढोने पर रोक लगाते हैं। भारत जैसे परिपक्व लोकतंत्र में यह व्यवहार अस्वीकार्य है, इस तथ्य के बावजूद कि यह अतीत में आम रहा होगा।
- सरल प्रशासन: यूसीसी भारत की विशाल जनसंख्या का प्रबंधन करना आसान बना देगा।

यूसीसी आलोचनाओं में शामिल हैं:

- भारतीय समाज की बहुसंस्कृतिवाद और विविधता बाधित होगी और इसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं गायब हो जाएंगी। इस राष्ट्र में कानूनी प्रणाली की ये विशिष्ट विशेषताएं एक संयुक्त के तहत गायब हो जाएंगी।
- क्योंकि उनका मानना है कि यह धार्मिक सरोकारों में हस्तक्षेप करेगा और संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा, धार्मिक संगठन समान नागरिक संहिता के विरोध में हैं।

अगले कदम:

- संविधान के मूल सिद्धांत विविधता का समर्थन करते हैं और सभी संप्रदायों के ईसाइयों के बीच सम्मान को बढ़ावा देते हैं।
- धीरे-धीरे समायोजन एकीकृत कानून आम तौर पर एक अच्छी बात है, लेकिन अगर इसे जल्दी से पारित किया जाता है, तो यह देश की अखंडता और एकता को खतरे में डाल सकता है।
- कानून के शासन के साथ लोकतंत्र में सुधार और व्यवस्था को धीरे-धीरे लागू किया जाना चाहिए।
- **स्रोत → हिन्दू**



4. - जीआई टैग का विवरण:

GS II

विषय→सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप:

➤ संदर्भ:

- ओणम के दौरान मांग में अप्रत्याशित वृद्धि और रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के कारण, केरल राज्य काजू विकास निगम (केएससीडीसी) ने केरल काजू के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के लिए एक आवेदन दायर करने का निर्णय लिया। पारंपरिक तरीके से उत्पादित ड्रम-भुने काजू के लिए मान्यता कई स्थानों पर मशीनीकृत प्रसंस्करण के अति प्रयोग के कारण उनकी दुर्लभता की ओर ध्यान आकर्षित करेगी।

के बारे में:

- भौगोलिक संकेतक टैग को भारत में "जीआई टैग" या "जीआई टैग" के रूप में भी जाना जाता है। यह कानून 15 सितंबर, 2003 से प्रभावी हो गया है।
- एक विशिष्ट भौगोलिक मूल और विशेषताओं या उस मूल से उत्पन्न प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं की पहचान एक भौगोलिक संकेतक (जीआई) का उपयोग करके की जाती है।
- ऐसा नाम एक प्रतिभा और विलक्षणता को प्रकट करता है जो ज्यादातर इसके मूल देश से संबंधित हैं।
- भौगोलिक रूप से ब्रांडेड उत्पादों को भारत में गौरवशाली राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व के रूप में अत्यधिक महत्व दिया जाता है।
- 10 साल बीत जाने के बाद इस टैग का नवीनीकरण किया जा सकता है।

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत के भौगोलिक संकेत (जीआई) के लिए नाम और लोगो की शुरुआत की।
- भारत की दार्जिलिंग चाय 2004 में जीआई लेबल दिए जाने वाला पहला उत्पाद था।
- माल के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में भौगोलिक संकेतों (जीआई) (जीआई अधिनियम) के संरक्षण के लिए कानून का एक नया टुकड़ा है।
- भारत, एक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौते का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम को मंजूरी दी।

जीआई टैग के लाभ:

- एक व्यक्ति उपयुक्त भौगोलिक संकेतक का उपयोग दूसरों को गैर-अनुपालन उत्पादों का समर्थन करने से रोकने के लिए कर सकता है यदि उनके पास यह है।

• स्रोत→ हिन्दू



संपादकीय विश्लेषण

1. पुलिस सुधार:

पुलिस सुधारों का महत्व और आवश्यकता:

- दुनिया भर में, प्रति 100,000 लोगों पर 270 पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन भारत में केवल 120 ही हैं। पुलिस और सबपर उपकरणों की कमी के कारण भारत के लोग दुनिया में सबसे कम सुरक्षित हैं, जो अक्सर नेताओं की रक्षा के लिए नियोजित होते हैं।
- भ्रष्टाचार: 2016 में, सतर्कता सेवा ने 2015 में अपने पुरुषों की तुलना में 55% अधिक जांच की। दिल्ली पुलिस के सर्वेक्षण के अनुसार, 2015 में केवल 34% पुलिस अधिकारी बेईमान थे, 2014 में 66% से नीचे।
- अपराध के विकसित होते स्वरूप आधुनिक सोशल मीडिया और इंटरनेट ने सामाजिक और तकनीकी प्रगति को तेज कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप भयानक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और अराजकता के पहले अनसुने स्तर हो गए हैं। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अपराध का प्रकार, सीमा और वेग बदल गया है।
- पुलिस कदाचार विश्वसनीय जवाबदेही तंत्र और नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन के अभाव में, पुलिस में जनता का विश्वास कम हो गया है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर सबसे हालिया भीड़ का हमला जनता के पुलिस के अविश्वास का सबसे अच्छा उदाहरण है।
- अपर्याप्त तकनीकी संसाधन पुलिस जांच की गुणवत्ता भारत की कम सजा दर के कारणों में से एक है। गहन

जांच के लिए आवश्यक अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण पुलिस के पास उपलब्ध नहीं हैं।

- उनके पास सहानुभूति की कमी है क्योंकि महिलाओं और वंचित पृष्ठभूमि के लोगों का प्रतिनिधित्व कम है। हिंसा में वृद्धि का श्रेय जातिगत तनावों को दिया जा रहा है, विशेष रूप से सबसे हालिया दलित विद्रोह और कृषि संबंधी मुद्दों को।
- कानून और व्यवस्था बनाए रखना एक पुलिस अधिकारी की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक है, लेकिन वे यातायात को भी नियंत्रित करते हैं, आपदा सहायता प्रदान करते हैं और अतिक्रमण हटाते हैं। इस वजह से उन्हें अधिक काम करना होगा। इन अतिरिक्त कर्तव्यों के परिणामस्वरूप पुलिस बल अधिक काम करता है, जिसका उनके उत्पादन और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

आगे बढ़ना:

- पुलिस बल को आज और कल के मुद्दों को संभालने के लिए आवश्यक जांच उपकरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया बुनियादी ढांचे के साथ प्रदान करने के लिए, आपराधिक न्याय प्रणाली और स्थानीय स्तर पर कानून प्रवर्तन संस्थानों को तत्काल आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।
- निचले स्तर के अधिकारियों पर ध्यान केंद्रित यदि निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों के पास बेहतर लाभ, वेतन और प्रशिक्षण है, और यदि एक प्रणाली स्थापित की जाती है जो बुरे व्यवहार के बजाय पहल और अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करती है, तो वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे।



- स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण: एक अलग शिकायत प्राधिकरण को पुलिस के गलत कामों के आरोपों की जांच करनी चाहिए। अपराधों की बेहतर जांच के लिए राज्यों को अपने पुलिस बलों के अंदर विशेष जांच इकाइयां बनानी चाहिए।
- पुलिस अधिकारियों के लिए अधिक लैंगिक समानता प्रशिक्षण की आवश्यकता है। महिलाओं को पुलिस में 33 फीसदी रिजर्व दिया जाना चाहिए।
- पुलिस सुधार की मांग का जवाब देने के लिए और अधिक राजनीतिक कर्षण की आवश्यकता है। तेलंगाना और केरल दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने प्रक्रिया को तेज करने के लिए कदम उठाए हैं।
- कानून प्रवर्तन, जांच और अपराध की रोकथाम स्थानीय राज्य पुलिस इकाइयों के मुख्य कर्तव्य हैं। त्वरित न्याय की गारंटी के लिए पुलिस बलों को फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण जैसे आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए।

GURU DEEKSHAA IAS



2. विदेशी मुद्रा भंडार:

- स्वर्ण भंडार, आईएमएफ के पास रखे गए एसडीआर, और केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्राओं में रखी संपत्तियां उन वस्तुओं में से हैं जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (भारत में, भारतीय रिजर्व बैंक) को बनाते हैं। विदेशी बैंक नोटों के अलावा, विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी ट्रेजरी बिल, विदेशी बैंक जमा, विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां और अन्य चीजें भी शामिल हैं। विदेशी मुद्रा भंडार एक सुरक्षा जाल और चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण स्थितियों के खिलाफ एक तकिया के रूप में कार्य करता है। इनका मौद्रिक नीति पर प्रभाव पड़ता है और इनका उपयोग स्थानीय मुद्रा-मूल्यवान देनदारियों का समर्थन करने के लिए किया जाता है। अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन और चीनी युआन उन अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं में से हैं जिन्हें विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में रखा जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार क्या हैं?

- केंद्रीय बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार भंडार के रूप में विभिन्न मुद्राओं की एक श्रृंखला में संग्रहीत बड़ी संपत्ति हैं।
- उन्हें अक्सर विनिमय दरों को नियंत्रित करने और मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए नियोजित किया जाता है।
- एक रूढ़िवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार, केवल विदेशी बैंकनोट, विदेशी ट्रेजरी बिल, विदेशी बैंक जमा, और लंबी और अल्पकालिक विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों को एफएक्स के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

- दरअसल, आईएमएफ रिजर्व पोजीशन, एसडीआर और गोल्ड रिजर्व को ध्यान में रखा जाता है। बाद के आंकड़े के लिए, जिसकी गणना करना आसान है, "अंतराष्ट्रीय भंडार" शब्द अधिक लागू होता है।

विदेशी मुद्रा भंडार रखने के लक्ष्य:

- मौद्रिक और विनिमय दर विनियमन तंत्र में विश्वास बनाए रखना और बढ़ाना
- आपको राष्ट्रीय या संघ मुद्रा की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है।
- आपात स्थिति के दौरान या जब उधार लेने की अनुमति नहीं है, तो झटके को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा तरलता बनाए रखकर बाहरी भेद्यता को कम करता है।

विदेशी मुद्रा भंडार रखना क्यों महत्वपूर्ण है

मुद्रा भंडार रखने का उद्देश्य है:

- अपनी मुद्राओं की विनिमय दरों को बनाए रखने के लिए।
- लचीली विनिमय दर व्यवस्था वाले देश में, विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग मुद्रा के मूल्य को अमेरिकी डॉलर से नीचे रखने के लिए किया जाता है।
- वित्तीय संकट की स्थिति में, तरलता बनाए रखने के लिए।
- बाजारों को स्थिर रखने के लिए, केंद्रीय बैंक (RBI) विदेशी मुद्रा जारी करता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक देश अपने दायित्वों और अन्य देशों के वादों को पूरा करता है।



विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने वाले कारक:

- भारतीय शेयरों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने के मुख्य चालक हैं।
- वित्त मंत्रालय की घोषणा कि 2019 में निगम कर की दरें कम की जाएंगी, भंडार में तेजी से वृद्धि हुई।
- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, विदेशी मुद्रा की भारी मात्रा में बचत के कारण तेल आयात अब कम खर्चीला है।
- प्रेषण और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा वर्तमान में देश छोड़ने के दो मुख्य कारण हैं।

विदेशी मुद्रा का भंडार जरूरी:

- सरकार को ऐसे समय में भारत की घरेलू और बाहरी वित्तीय चिंताओं का प्रबंधन करने की आरबीआई की क्षमता से लाभ होता है जब जीडीपी गिर रहा है (23.9 प्रतिशत) और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है।
- यह सरकार को विदेशी मुद्रा एकत्र करने और अन्य देशों को अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करता है।
- रुपये में मजबूती: डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है।

Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are



Vijay Kumar G

Founder and Director
Guru Deekshaa IAS

-  First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
-  Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
-  Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

 **76 76 74 98 77**

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

 @GURU_DEEKSHAAIAS



FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

 GURUDEEKSHAA

